कभी वेतन देने के पैसे नहीं थे, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना यूपी : योगी

फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले सीएम-यूपी अब बीमारू नहीं

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद किसानों के कर्ज माफी जैसे प्रस्तावों के लिए धन की कमी थी। उस समय बैंकों का सहयोग नहीं मिलता था और कर्मचारियों के वेतन के लिए भी संसाधन नहीं थे। उत्तर प्रदेश कभी अपने कर्मचारियों को वेतन देने की भी स्थिति में नहीं था। लेकिन सरकार ने बजट में 36 हजार करोड़ रुपये की लिकेज को चिह्नित कर उसे समाप्त किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बन गया है। यूपी अब बीमारू नहीं, बल्कि देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। राज्य ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता हासिल की है।

सीएम योगी ने इस अवसर को अहम बताते हुए कहा कि आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। फिक्की को उत्तर प्रदेश के विकास में अहम साझेदार बताते हुए कहा कि इस संगठन ने निवेशकों के लिए सकारात्मक माहौल और ईको-सिस्टम बनाने में सरकार का साथ दिया है। विशेष रूप से इन्वेस्टर्स समिट 2018 और 2023 को सफल बनाने में फिक्की का योगदान सराहनीय रहा है।

प्रदेश में है कानून का राज : सीएम ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण लोग अपनी पहचान छिपाने को मजबूर थे। महाकुंभ के उदाहरण से समझाया कि 2017 से पहले कुंभ में गंदगी और अव्यवस्था थी, लेकिन इस बार स्वच्छता और सुव्यवस्था ने सबका ध्यान खींचा। आज पूरे राज्य में कानून का शासन है। अनावश्यक लाउडस्पीकरों को हटाया गया, सड़कों पर धार्मिक आयोजन को नियंत्रित किया गया और बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

कभी प्रदेश छोड़ने को तैयार कंपनियां आज कर रहीं यूपी में निवेश : सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें चल रही हैं और गन्ना किसानों को 3 से 7 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। पिछले आठ वर्षों में डीबीटी से गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में हुआ है। 2017 में जब सैमसंग और टीसीएस जैसी कंपनियां उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार थीं, तब सरकार ने उन्हें विश्वास दिलाया और आज तो 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयनका और उत्तर प्रदेश फिक्की के अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित देशभर के उद्यमी उपस्थित रहे।

सीएम योगी ने सोमवार को फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को संबोधित किया।

'कभी उद्यमी यूपी में आने से डरते थे, आज बना ड्रीम डेस्टिनेशन'

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 33 सेक्टोरियल नीतियों और निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 500 से ज्यादा मंजूरियां सिंगल विंडो सिस्टम से दी जा रही हैं। एमएसएमई को पुनर्जीवित किया गया और उद्यमियों के अनावश्यक उत्पीड़न को खत्म किया गया। उन्होंने एक उदाहरण साझा किया कि 2017 में मुंबई में एक उद्यमी ने उनसे सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। उस उद्यमी ने बाद में 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया और 2023 में उत्तर प्रदेश को निवेश का 'ड्रीम डेस्टिनेशन' बताया।

महाकुंभ का सफल आयोजन यूपी की क्षमता का प्रतीक

सीएम ने महाकुंभ के सफल आयोजन को उत्तर प्रदेश की क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में साढ़े सात हजार करोड़ रुपये खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प किया गया। महाकुंभ को लेकर विपक्षी सवाल उठाते थे, पूछते थे कि क्या महाकुंभ करवाना सरकार का कार्य है। मगर आप सभी ने देखा होगा कि महाकुंभ केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे शहरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।